OBTAIN YOUR OWN ISP LICENSE

The Internet provides information to students, entertainment to the home and facilitates business and communication. As a result, most computers today want to be connected to the internet.

Today, internet services provide an excellent business opportunity, with large margins. While the cable TV business typically offers margins of 30 to 50%, internet services provide margins of 300% to 500%. We therefore urge all cable TV MSOs and LCOs to diversify their business to include providing internet services. Before you can commence providing internet services, you must obtain an internet service provider's licence from the Department of Telecom (DoT) in New Delhi.

Internet Services Today Provide Margins Of Over 300%

Lets us first understand a few basic concepts about the internet & broadband.

THE INTERNET

The internet is simply a large network of computers. Any computer can join the internet using basic hardware and software which are usually built into every computer sold today.

ISP

A company that provides an Internet connectivity, is an Internet Service Provider (ISP).

INTERNET SPEED

The speed at which your computer can send information to or receive information from the internet is the speed of your internet connection.

BROADBAND

If your computer is connected to the internet at all times at a particular minimum speed, it is called a broadband connection.

MINIMUM BROADBAND SPEED

In India, a broadband connection must have a minimum download speed of 512 KBPs. Most

अपने खुद का आईएसपी लाइसेंस प्राप्त करें

इंटरनेट छात्रों को सूचना, घर के लिए मनोरंजन और व्यापार व संचार की सुविधा प्रदान कर रहा है। परिणामस्वरूप आज अधिकतर कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं।

आज इंटरनेट सेवा अच्छी मार्जिन के साथ उत्कृष्ट व्यापार का अवसर प्रदान कर रहा है। हालांकि केवल व्यवसाय आमतौर पर 30 से 50 % का मार्जिन ऑफर करता है, वहीं इंटरनेट सेवा 300 से 500% का मार्जिन प्रदान करता है। इसलिए हम सभी केबल टीवी एमएसओ व एलसीओ से आग्रह करेंगे की वे अपने व्यवसाय में विविधता लाते हुए इंटरनेट सेवा प्रदान करें। इंटरनेट सेवा शुरू करने से पहले आपको दूरसंचार विभाग (डॉट), नयी दिल्ली से इंटरनेट सेवा प्रदायक का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

आज इंटरनेट सेवा 300% से अधिक की मार्जिन प्रदान कर रहा है

आइये सबसे पहले इंटरनेट व ब्रॉडबैंड के बारे में कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझ लें।

इंटरनेट

इंटरनेट आमतौर पर कंप्यूटर का बड़ा नेटवर्क है। कोई भी कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इंटरनेट शामिल कर सकता है जो कि आमतौर पर आज बेचे जाने वाले सभी कंप्यूटर में पहले से ही लगा रहता है।

आईएसपी

इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली कंपनी को इंटरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कहा जाता है।

इंटरनेट स्पीड

जिस स्पीड पर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से सूचना को भेज या प्राप्त कर सकता है वह आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है।

ब्रॉडबैंड

यदि आपका कंप्यूटर खास न्यूनतम स्पीड के साथ हर समय इंटरनेट से जुड़ा रहता है तो इसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है।

न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड

भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की न्यूनतम स्पीड 512 KBps होनी चाहिए। आज विश्व में अधिकतर देशों को 2 MBps यानि

countries in the world today require a broadband speed of minimum of 2 MBps i.e. 2,000 KBps.

Hence every ISP in India must maintain a minimum speed of 512 KBps. Some ISPs offer unlimited usage of the Internet, even after the consumer depletes his monthly download + upload quota. Even in such cases, a Broadband service provider must maintain a speed of atleast 512 KBps.

DOWNLOAD & UPLOAD

The download speed refers to speed that the data connection delivers from the internet to your computer. The upload speed is the speed at which your computer is allowed to feed its data into the internet. A company that provides connectivity between the internet and your computer is referred to as an Internet Service Provider (ISP).

WIRED CONNECTION

Computers can connect to the internet using a wired connection. These are referred to as 'Wireline Subscribers.'

Wired Internet Must Be Atleast 50 MBps To Be Competitive

WIRELESS CONNECTION

Wireless Internet Subscribers connect to the internet either through their mobile phones or other wireless technologies such as WIFI inside their homes. Out of a total of 368 million Indian internet subscribers, 346 million are wireless. Only 21 million (5.7% of total) subscribers are wireline subscribers.

WIRED & WIRELESS SPEEDS

Wireless subscribers such as mobile phone users have internet access even when they are on the go. However, Wireless Internet is usually delivered at a much lower speed than wired or wireline internet. New wireless technologies such as mobile 4G provide fast internet access of upto 50 MBps. Hence wireline internet services must provide internet connectivity at atleast 50 MBps or more to remain competitive with new technologies like 4G wireless. A wired connection can provide speeds of 1000 MBps (1GBPs) and higher.

Mobile Wireless services can be offered only by telecom licence holders, which is extremely expensive.

2,000 KBps की न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड की जरूरत होती है। इसलिए भारत में प्रत्येक आईएसपी को **512** KBps की न्यूनतम स्पीड को बरकरार रखना चाहिए। कुछ आईएसपी इंटरनेट के अनलिमिटेड इस्तेमाल का ऑफर देते हैं, बावजूद इसके कि उपभोक्ता अपने मासिक डाउनलोड + अपलोड कोटा को पार कर लेता है। इस तरह के मामले में भी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदायक को कम से कम **512** KBps की स्पीड को बनाये रखना पड़ता है।

डाउनलोड व अपलोड

डाउनलोग स्पीड का उल्लेख उस स्पीड के रूप में किया जाता है जिसपर की डेटा कनेक्शन आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से डिलिवर करता है। अपलोड स्पीड वह स्पीड है जिस पर की आपका कंप्यूटर इंटरनेट में अपने डेटा को फीड करने की अनुमति देता है। एक कंपनी जो कि इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के वीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है उसे इंटरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) के रूप में जाना जाता है।

वायरड् कनेक्शन

कंप्यूटर को वायरड् कनेक्शन का इस्तेमाल करके इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसे 'वायरलाइन सब्सक्राइवर्स' के रूप में जाना जाता है।

*वायरड इंटरनेट को प्रतिस्पर्धी होने के लिए कम से कम **50** MBps का होना चाहिए*

वायरलेस कनेक्शन

वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइवर, इंटरनेट को अपने मोबाइल फोन की सहायता से या अपने घरों के भीतर वाई-फाई जैसी अन्य वायरलेस तकनीकी की सहायता जुड़े हो सकते हैं। कुल **368** मिलियन भारतीय इंटरनेट उपभोक्ताओं में से **346** मिलियन वायरलेस हैं। मात्र **21** मिलियन (कुल के 5.7%) सब्सक्राइवर ही वायरलाइन सब्सक्राइवर हैं।

वायरड् व वायरलेस स्पीड

मोबाइल फोन इस्तेमालकर्ताओं जैसे वायलेस सब्सक्राइवर यात्रा के दौरान भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि वायरलेस इंटरनेट आमतौर पर वायरलाइन इंटरनेट या वायरड् के मुकाबले काफी कम स्पीड डिलिवर करता है। मोबाइल **4**जी जैसे नये वायलेस तकनीकी **50** MBps तक की फॉर्स्ट इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। इसलिए वायरलाइन इंटरनेट को **4** जी वायरलेस जैसी नयी तकनीकी के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कम से कम **50** MBps या इससे अधिक की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करनी होगी। वॉयरड् कनेक्शन **1000** MBps (**1** GBps) और इससे अधिक की स्पीड प्रदान कर सकता है।

मोबाइल वायरलेस सेवा सिर्फ टेलीकॉम लाइसेंस संचालकों द्वारा ही ऑफर किया जा सकता है, जो कि काफी महंगा होता है।

ISP LICENSE

ISP LICENSE

Wired Internet can be provided by anyone holding an Internet Service Provider's (ISP) license.

> *There Are 3 Categories Of ISP Licenses*

ISP LICENSE CATEGORIES

The Internet Service Provider's (ISP) license is issued by the Department of Telecom (DoT) in New Delhi.

There are 3 levels of ISP licences viz:

- The ISP-A license permits the company to provide internet services anywhere within the country.
- The ISP-B license allows a company to provide internet services in any one of the 4 Metro cities: New Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai or any of the 16 telecom circles. Typically, each state is defined as a Telecom circle.
  Table-1 provides a listing of all 16 Telecom circles + 4 Metro Circles.
- ISP-C - This effectively covers ISP services in all areas not listed in the ISP-B category.

A company can also apply for an ISP License to cover more than 1 area. If it selects 4 areas under the ISP-C category, it will have to apply for an ISP-B category license.

ISP LICENSE CONDITIONS

An ISP license is granted for a period of 20 years.

The license holder must commence commercial operations with 18 months of receiving the license.

The application form is to be bought from DoT for ₹ 1,000 and the processing fee is ₹ 5,000.

> *ISP Licenses Are issued only To Registered Companies, Not Individuals*

LICENSE APPLICATION

Table-2 summarises the Entry Fee and the Bank Guarantees that an ISP applicant must submit along with his license application.

The cost of an ISP C category license is well within the means of LCOs and MSOs, enabling them

आईएसपी लाइसेंस

वायरड् इंटरनेट कोई भी जिसके पास इंटरनेट सर्विस प्रदायक (आईएसपी) का लाइसेंस हो, प्रदान कर सकता है।

> *आईएसपी लाइसेंसों की 3 श्रेणियां हैं*

आईएसपी लाइसेंस श्रेणियां

इंटरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाइसेंस को नयी दिल्ली में दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा जारी किया जाता है।

आईएसपी लाइसेंस 3 स्तर के होते हैं, जैसेः

- आईएसपी–ए लाइसेंस, कंपनी को देश के भीतर कहीं भी इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है।
- आईएसपी–बी लाइसेंस कंपनी को नयी दिल्ली, मुंवई, कोलकाता व चेन्नई में से किसी एक या 16 टेलीकॉम सर्किलों में से कहीं भी इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है। आमतौर पर हर राज्य को टेलीकॉम सर्किल के रूप में परिभाषित किया गया है। टेवल–1 सभी 16 टेलीकॉम सर्किल + 4 मेट्रो सर्किलों की सूची प्रदान करता है।
- आईएसपी–सी– यह आईएसपी–बी श्रेणी में नहीं सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली तरीके से आईएसपी सेवाओं को कवर करता है।

एक कंपनी एक से अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए आईएसपी लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकता है। यदि यह आईएसपी–सी श्रेणी के तहत 4 क्षेत्रों का चुनाव करता है तो यह आईएसपी–बी श्रेणी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा।

आईएसपी लाइसेंस शर्तें

एक आईएसपी को 20 वर्षो की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस धारक को लाइसेंस प्राप्त होने के 18 महीने के भीतर वाणिज्यिक सेवाओं को शुरू करना चाहिए। आवेदन फॉर्म को 1000 रुपये में डॉट से खरीदा जा सकता है और प्रोसेसिंग शुल्क 5000 रुपये है।

> *आईएसपी लाइसेंस सिर्फ पंजीकृत कंपनियों को जारी किया जाता है, न कि व्यक्ति विशेष को*

लाइसेंस आवेदन

टेवल–2 में एंट्री शुल्क व बैंक गारंटी को संक्षेप में दिया जा रहा है जिसे कि आईएसपी आवेदक को लाइसेंस आवेदन के साथ निश्चित रूप से जमा करना होगा।

आईएसपी सी श्रेणी लाइसेंस की लागत एलसीओ व एमएसओ के

ISP LICENSE

No.	TELECOM CIRCLE
1	West Bengal Includes Andaman & Nicobar Islands & Sikkim. Excludes Kolkata
2	Andhra Pradesh
3	Assam
4	Bihar Includes Jharkhand
5	Gujarat Includes Daman, Diu & Silvassa (Dadra & Nagar Haveli)
6	Haryana Excludes Panchkula, Faridabad & Gurgaon
7	Himachal Pradesh
8	Jammu & Kashmir Service Includes Ladakh.
9	Karnataka
10	Kerala Includes Lakshadeep & Minicoy.
11	Madhya Pradesh Includes Chattisgarh
12	Maharashtra Includes Goa. Excludes Mumbai
13	North East Includes Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur & Tripura.
14	Orissa
15	Punjab Includes Chandigarh & Panchkula
16	Rajasthan
17	Tamilnadu Includes Chennai & Pondichery
18	Uttar Pradesh (West)
19	Uttar Pradesh (East)
20	Delhi Includes Ghaziabad, Faridabad, Noida & Gurgaon
21	Kolkata
22	Mumbai

Table-1: List Of 22 Telecom Circles

नं	टेलीकॉम सर्किल
1	पश्चिम बंगाल अंडमान व निकोबार द्वीप व सिक्किम शामिल, कोलकाता को छोड़कर
2	आंध्र प्रदेश
3	असम
4	विहार झारखंड शामिल
5	गुजरात दमन, द्वीप व सिलवासा सहित (दादरा व नगर हवेली)
6	हरियाणा पंचकूला, फरीदाबाद व गुडगांव को छोड़कर
7	हिमाचल प्रदेश
8	जम्मू एंड कश्मीर सर्विस लद्दाख शामिल
9	कर्नाटक
10	केरल लक्षद्वीप व मिनीकॉय सहित
11	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित
12	महाराष्ट्र गोवा के साथ, मुंबई छोड़कर
13	उत्तर पूर्व अरूणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर व त्रिपुरा के साथ
14	उड़ीसा
15	पंजाव चंडीगढ़ व पंचकुला के साथ
16	राजस्थान
17	तमिलनाडु चेन्नई व पांडिचेरी सहित
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
20	दिल्ली गाजियावाद, फरीदाबाद, नोयडा व गुड़गांव सहित
21	कोलकाता
22	मुंबई

टेबल–1ः 22 टेलीकॉम सर्किलों की सूची

ISP LICENSE

	AGR Payment	Entry Fee	Performance Bank Guarantee	Financial Bank Guarantee	Application Fee
ISP Category A (National)	8%	₹ 30 Lakhs	₹ 2 Crores	₹ 10 Lakhs	₹ 50,000
ISP Category B (Metros or Telecom Circle)	8%	₹ 2 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 1 Lakhs	₹ 15,000
ISP Category C (Non ISP B Areas)	8%	₹ 20,000	₹ 50,000	₹ 10,000	₹ 10,000

Table 2 *: Fees & Bank Guarantees Required To Apply For An ISP License.*

	शुल्क एजीआर	प्रवेश शुल्क	प्रदर्शन बैंक गारंटी	फाइनेंशियल बैंक गारंटी	आवेदन शुल्क
आईएसपी श्रेणी ए (राष्ट्रीय)	8%	30 लाख रु	2 करोड़ रु	10 लाख रु	50,000 रु
आईएसपी श्रेणी बी (मेट्रो या टेलीकॉम सर्किल)	8%	2 लाख रु	10 लाख रु	1 लाख रु	15,000 रु
आईएसपी श्रेणी सी (गैर आईएसपी बी क्षेत्र)	8%	20,000 रु	50,000 रु	10,000 रु	10,000 रु

टेबल 1ः आईएसपी लाइसेंस की लागत

to venture into this business diversification into the lucrative area of distribution Broadband services in their territory.

It is important to note the following:

1. ISP Licenses are issued Only to Registered Companies, Not individuals.
2. There is No minimum equity or minimum net worth requirement For ISP companies.
3. An ISP license is supposed to be issued within 60 days.

LICENCE FEE

Just as an MSO or LCO is required to pay a license fee, there is also a fee payable for the ISP license. While the MSO/LCO is required to pay a one-time license fee, the Government has imposed an annual license fee for ISPs, in addition to a one-time Entry Fee. This is similar to what is levied on DTH platforms.

ISP ANNUAL LICENCE FEE

The ISP license fee is 8% of the Adjusted Gross Revenue (AGR) of the ISP license holder.

Hence if the ISP has an annual business/ revenue of ₹ 50,00,000 + Service Tax, he is required to pay a license fee of 8% of ₹ 50 Lakhs, i.e. ₹ 4,00,000

अर्थ के भीतर सही तरीके से बैठता है, जो कि उन्हें उनके क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं के वितरण के आकर्षक क्षेत्र में इस व्यवसाय के विविधीकरण के भीतर आने में सक्षम बनाता है।

निम्न बातों को नोट करना महत्वपूर्ण हैः

1. आईएसपी लाइसेंस सिर्फ पंजीकृत कंपनियों को जारी किया जाता है, न कि व्यक्ति विशेष को।
2. आईएसपी कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम इक्विटी या न्यूनतम नेटवर्थ की जरूरत नहीं होती है।
3. आईएसपी लाइसेंस 60 दिनों के भीतर जारी होना चाहिए।

लाइसेंस शुल्क

जैसे एमएसओ या एलसीओ के लिए लाइसेंस शुल्क भुगतान करने की जरूरत है वैसे ही आईएसपी लाइसेंस के लिए भी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि एमएसओ/एलसी को एकबार लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने आईएसपी के लिए एक बार एंट्री शुल्क के अलावा वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी लागू किया है। यह बिल्कुल वैसी ही उगाही है जैसाकि डीटीएच प्लेटफार्म पर लगाया जाता है।

आईएसपी वार्षिक लाइसेंस शुल्क

आईएसपी लाइसेंस शुल्क, आईएसपी लाइसेंस धारक के समायोजिक सकल राजस्व (एजीआर) के 8% है। इसलिए यदि आईएसपी का वार्षिक बिजनेस/राजस्व 50,00,000 + सर्विस टैक्स है, तो उसे 50 लाख रुपये के 8% का लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा, यानि कि

as his annual license fee. No license fee is payable on the Service Tax amount.

ISPs Must Pay 8% Of Revenues As A License Fee

The AGR is calculated on the total revenue, so it would include even equipment that the ISP may sell to the consumer, or repair charges.

There are no deductions, even for the cost of Bandwidth purchased by the ISP.

AGR & FRANCHISEES

It is very relevant to discuss the role of an ISP franchisee, and the tax payable in such cases. Several cable networks show themselves as franchisees of an ISP, making the issue particularly important for our industry.

A franchisee takes internet bandwidth from an ISP. The cable network provides broadband connections to individual users as a franchisee of a licensed ISP. As an example, a cable network may take its broadband connection from RailTel and distribute these signals to end consumers without the cable network itself obtaining an ISP license. (Note: *RailTel is only taken as an illustrative example. it applies to any other licensed ISP, with a Category A or Category B or Category C license.*) The cable network says it is a franchisee of RailTel and RailTel has an ISP license.

The End Consumer Must Be Invoiced By The ISP, Not The Franchisee

In such a case, the cable network as a franchisee must strictly adhere to the following:

1. The service must be provided to the end consumer as a RailTel service under the RailTel branding.
2. The invoice must be raised on the end consumer as a RailTel invoice.
3. The revenues from each subscriber must be accounted for by RailTel.
4. RailTel must pay 8% AGR on the amount collected from each retail subscriber even of the broadband network operated by the Cable operator.

4,00,000 रुपये उसका वार्षिक लाइसेंस शुल्क होगा। सर्विस टैक्स रकम पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

आईएसपी को लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व के 8% का भुगतान करना होगा

एजीआर की गणना कुल राजस्व पर की जायेगी, जिससे कि इसमें उपकरण भी शामिल होंगे, जिसे कि आईएसपी शायद उपभोक्ता को वेचे या मरम्मत शुल्क ले। आईएसपी द्वारा खरीदे गये बैंडविड्थ की लागत के लिए भी कोई कटौती नहीं होगी।

एजीआर व फ्रैंचाईजी

यह बहुत प्रासंगिक होगा कि आईएसपी फ्रैंचाईजी की भूमिका और इस तरह के मामले में देय कर के बारे में चर्चा की जाये। कई केबल ऑपरेटर अपने आपको एक आईएसपी का फ्रैंचाईजी बताते हैं, जो कि हमारे उद्योग के लिए मामले को खासकर महत्वपूर्ण बना देती है।

एक फ्रैंचाईजी एक आईएसपी से इंटरनेट बैंडविड्थ लेता है। केबल नेटवर्क, लाइसेंस धारक आईएसपी के फ्रैंचाईजी के रूप में व्यक्तिगत इस्तेमालकर्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में एक केबल नेटवर्क, रेलटेल से अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को ले सकता है और केबल नेटवर्क के खुद किसी तरह का आईएसपी लाइसेंस प्राप्त किये विना अपने उपभोक्ताओं को इन सिगनलों को वितरित कर सकता है। (नोटः *रेलटेल का नाम सिर्फ उदाहरण के लिए लिया जा रहा है, यह श्रेणी ए या श्रेणी बी या श्रेणी सी लाइसेंस के साथ किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त आईएसपी के लिए लागू होगा*)। केबल नेटवर्क कह सकते हैं कि वे रेलटेल के फ्रेंचाईजी हैं और रेलटेल के पास आईएसपी लाइसेंस है।

अंतिम उपभोक्ताओं को आईएसपी द्वारा इनवॉयस दिया जायेगा, न कि फ्रैंचाईजी की ओर से

इस तरह के मामले में केबल नेटवर्क को फ्रैंचाईजी के रूप में निम्न बातों का सख्ती से पालन करना होगाः

1. सेवा को रेलटेल ब्रॉन्डिंग के तहत रेलटेल सेवा के रूप में अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करना होगा।
2. इनवॉयस निश्चित रूप से रेलटेल इनवॉयस के रूप में उपभोक्ताओं को जारी किया जायेगा।
3. प्रत्येक उपभोक्ता से राजस्व का लेखा जोखा रेलटेल द्वारा किया जाना चाहिए।
4. रेलटेल को केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क संचालन करने के वावजूद प्रत्येक खुदरा उपभोक्ताओं से राशि जमा करना होगा।

HUGE FINANCIAL IMPACT

The above imply a huge financial impact which is often, knowingly or unknowingly ignored by the retailing broadband network.

Let us assume that the cable operator purchases band width from RailTel and pays RailTel ₹ 50,000 per month for the bandwidth.

This bandwidth is then retailed by the cable operator's broadband network to end consumers, for a total of ₹ 3,00,000 per month. RailTel's license terms require RailTel to pay a licence fee of 8% of the ₹ 3,00,000 collected from subscribers and not on the ₹ 50,000 that RailTel has charged the broadband network/retailer for its bulk bandwidth.

Since broadband retailing is a high profit margin business, the tax which is to be paid on the retail price rather than on any intermediate wholesale price of bandwidth, is quite different and a substantial amount of tax is payable.

The cable operator operating as a RailTel (or any other ISP) franchisee can be booked for tax evasion if they do not pay the 8% AGR on the retail price collected.

CATV & ISP Should Be Operated By Separate Companies

ISP + CABLE TV NETWORK

Another very important issue arises when a cable network also operates as an ISP. The same company may hold both a cable TV license + an ISP license.

Unfortunately, the ISP license rules state that the entire company's revenues/turnover will be used to compute the 8% AGR due on the ISP license.

Hence if an MSO (or LCO) operates both cable TV and broadband networks under the same company name, the MSO will not only have to pay cable TV entertainment tax + cable TV service tax but also an additional 8% of the entire cable TV revenues, as the ISP license fee!

As a result of this, MSOs now operate separate companies for their cable TV and broadband activities. For example, Hathway Cable and Datacom Ltd. has decided to spin off its Cable TV business into a wholly owned subsidiary: 'Hathway Datacom Central Pvt Ltd.'. It will retain its broadband business in the parent company.

भारी वित्तीय प्रभाव

उपरोक्त बातों से काफी वित्तीय प्रभाव का संकेत मिलता है, जिसकी कि प्रायः खुदरा ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा जनबूझकर या अनजाने में अनदेखी की जाती है।

आइये मान लेते हैं कि केबल ऑपरेटर ने रेलटेल से बैंडविड्थ खरीदी और बैंडविड्थ के लिए वे रेलटेल को **50,000** रुपये प्रति महीने का भुगतान करते हैं। इसके बाद बैंडविड्थ को कुल **3,00,000** रु प्रति माह की दर से अंतिम उपभोक्ताओं को केबल ऑपरेटरों के बॉडबैंड नेटवर्क द्वारा खुदरा में दिया जाता है। रेलटेल के लाइसेंस शर्तो के मुताविक उसे सब्सक्राइबरों से एकत्रित **3,00,000** रुपये के **8%** का भुगतान लाइसेंस शुल्क के रूप में करना होगा और न कि **50,000** रुपये पर, जो कि वह अपने थोक बैंडविड्थ के लिए खुदरा विक्रेताओं/ब्रॉडबैंड नेटवर्को से वसूल रहा है।

चूंकि ब्रॉडबैंड की खुदरा बिक्री एक उच्च लाभ मार्जिन वाली व्यवसाय है, इसलिए कर, जिसे कि खुदरा मूल्य पर भुगतान करना पड़ता है न कि बैंडविड्थ के किसी भी मध्यवर्ती थोक मूल्य पर, काफी भिन्न है और काफी मात्रा में कर का भुगतान करना पड़ता है। रेलटेल (या किसी अन्य आईएसपी) के फ्रैंचाईजी के रूप में केबल ऑपरेटरों को उस हाल में कर की चोरी के लिए बुक किया जा सकता है, यदि वे उनके द्वारा एकत्र किये गये खुदरा मूल्य पर **8%** एजीआर का भुगतान नहीं करते हैं।

सीएटीवी व आईएसपी को अलग कंपनियों द्वारा संचालित किया जायेगा

आईएसपी + केबल टीवी नेटवर्क

जब केबल नेटवर्क, आईएसपी के रूप में भी संचालन करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। समान कंपनी केबल टीवी लाइसेंस + एक आईएसपी लाइसेंस दोनों को संभाल सकती है।

दुर्भाग्य से आईएसपी नियम बताता है कि पूरी कंपनी का राजस्व/टर्नओवर का इस्तेमाल आईएसपी लाइसेंस पर देय **8%** एजीआर की गणना के लिए किया जायेगा।

इसलिए यदि एक एमएसओ (या एलसीओ) एक ही कंपनी के तहत दोनों केबल टीवी व ब्रॉडबैंड नेटवर्क का संचालन कर रहा है तो एमएसओ को न सिर्फ केबल टीवी मनोरंजन कर + केबल टीवी सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा बल्कि आईएसपी लाइसेंस शुल्क के रूप में पूरे केबल टीवी राजस्वों के अतिरिक्त **8%** का भी भुगतान करना होगा! इसके परिणामस्वरूप एमएसओ अब अपने केबल टीवी व ब्रॉडबैंड गतिविधियों के लिए अलग कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हेथवे केबल व डेटाकॉम लि. ने अपने केबल टीवी व्यवसाय को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'हेथवे डेटाकॉम सेंट्रल प्रा.लि.' में स्पिन ऑफ करने का फैसला किया है। जबकि ब्रॉडबैंड व्यवसाय मूल कंपनी में बनी रहेगी।

ISP LICENSE

Similarly, DEN Networks Limited provides Cable TV while Skynet - a separate company, fully owned by DEN operates the broadband business.

LEASING FIBRE

There are various other business synergies that can be shared between a cable TV network and an ISP.

Cable TV networks lay multicore optical fibre throughout their area of operation. Typically, there are several dark fibres within the fibre bundle. These could be very profitably leased out or sold for data or internet connectivity for example, between two office locations of a company within the same town.

The cable TV network will have to transfer the dark fibre to the broadband company (which also could be owned by the cable TV company). The ISP license holder can lease out this fibre to a data customer.

Using its skills in laying optical fibre gained through cable TV operations, the ISP company could also undertake, on a contract basis, laying a fresh fibre to provide point-to-point data connectivity to commercial establishments/companies within the town. According to current law, only an ISP license holder is permitted to lay and/or lease data cables/fibres.

Clearly, an ISP license opens up multiple commercial opportunities.

Laying / Leasing Data Cables / Fibre requires An ISP License

FACILITATING BROADBAND VIA CABLE

MSOs have highlighted the ISP AGR issue with the Government pointing out that it is a major impediment for delivering broadband via existing cable operators and networks.

For the past several years, the TRAI has been promising to resolve this matter with the DoT. In fact, the current TRAI Chairman has said that it is a priority for TRAI to facilitate broadband delivery to almost 100 million existing cable TV homes.

Let us hope for some positive response from the government that will facilitate and encourage Cable TV networks to offer broadband also to the 100 million Indian homes that they already service. ■

इसी तरह डेन नेटवर्क लिमिटेड भी केवल टीवी प्रदान कर रही है जबकि डेन द्वारा पूर्णतया संचालित एक अलग कंपनी स्काईनेट ब्रॉडबैंड व्यवसाय की देखरेख करती है।

फाइबर की लीजिंग

यहां पर कई अन्य बिजनेस रणनीतियां हैं जिसकी हिस्सेदारी केवल टीवी नेटवर्कों व आईएसपी के बीच की जा सकती है।

केवल टीवी नेटवर्क अपने संचालन के पूरे क्षेत्रों में मल्टीकोर ऑपटिकल फाइबर लगाते हैं। आमतौर पर फाइबर बंडल के भीतर कई डॉर्क फाइबर होते हैं। इसे डेटा या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बेचने या लीज पर देना काफी फायदेमंद होता है, उदाहरण के लिए एक ही शहर के भीतर कंपनी के दो स्थानों पर ऑफिस के बीच।

केवल टीवी नेटवर्क को डॉर्क फाइबर को ब्रॉडबैंड कंपनी (जिसे कि केवल टीवी कंपनी द्वारा स्वामित्व में भी किया जा सकता है) को ट्रांसफर करना होगा। आईएसपी लाइसेंस धारक इस फाइबर को डेटा उपभोक्ताओं को लीज पर दे सकता है।

ऑपटिकल फाइबर बिछाने में अपने कौशल का उपयोग केवल टीवी के संचालक के माध्यम से प्राप्त करके आईएसपी कंपनी भी अनुबंध के आधार पर इसे लेकर शहरों के भीतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/कंपनियों को प्वाइंट-टू-प्वाइंट डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नये फाइबर बिछा सकती हैं। वर्तमान कानून के मुताबिक सिर्फ आईएसपी लाइसेंस धारकों को ही डेटा केबल/फाइबर को लगाने/लीज पर देने की अनुमति है। साफतौर पर आईएसपी लाइसेंस एक से अधिक वाणिज्यिक संभावनाएं प्रदान कर रही हैं।

डेटा केबल/फाइबर को बिछाने/लीज पर देने के लिए आईएसपी लाइसेंस की जरूरत है

केबल की सहायता से ब्रॉडबैंड की सुविधा

एमएसओ ने वर्तमान केबल ऑपरेटरों व नेटवर्कों की सहायता से ब्रॉडबैंड की डिलिवरी के लिए महत्वपूर्ण वाधा के रूप में सरकार के सामने आईएसपी एजीआर मामले का उल्लेख किया है।

पिछले कई वर्षों से ट्राई ने डॉट के साथ इस मामले को हल करने का वादा किया है। वास्तव में ट्राई के मौजूदा अध्यक्ष ने बताया कि ट्राई के लिए यह प्राथमिकता होगी कि वह लगभग 100 मिलियन मौजूदा केवल टीवी घरों को ब्रॉडबैंड की डिलिवरी की सुविधा प्रदान करे।

आइये सरकार से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करें जो कि केवल टीवी नेटवर्कों को सुविधा और प्रोत्साहित करेगा कि वह 100 मिलियन भारतीय घरों को भी ब्रॉडबैंड ऑफर करे जिसे कि वह पहले ही सेवा दे रहा है। ■